Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/Pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
23 दिसंबर 2019

उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट के ख़िलाफ पुलिस की साज़िश
संगठन की केंद्रीय सचिवालय ने की निंदा;
गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सचिवालय की बैठक में संगठन के ख़िलाफ उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार की साज़िश की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। राज्य में संगठन के कार्यकर्ताओं को सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ आवामी विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी घटनाओं में ग़लत तरीके से फंसाया गया है। प्रदेश एड्हॉक कमेटी के कन्वीनर वसीम अहमद और अन्य सदस्यों क़ारी अशफाक़ और मोहम्मद नदीम को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, अब उनपर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें मीडिया के सामने हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर पेश किया जा रहा है। पुलिस ने इनमें से दो का चेहरा ढककर उन्हें मीडिया के सामने पेश किया, ताकि इस पूरे मामले के पीछे आतंकवाद का माहौल तैयार किया जा सके। पुलिस की यह कार्यवाही दरअसल प्रदेश उपमुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोप की एक कड़ी है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सभी अशुभ घटनाओं के पीछे पॉपुलर फ्रंट का हाथ है। केंद्रीय सचिवालय ने राज्य सरकार से राजनीतिक इंतकाम को बंद करने, सभी झूठे मुकदमों को वापस लेने और गिरफ्तार पदाधिकारियों को तत्काल रुप से रिहा करने की मांग की है।

केंद्र सरकार की जन–विरोधी पॉलिसियों के खिलाफ आवाम के गुस्से से बेचैन होकर, बीजेपी की राज्य सरकारें अवामी प्रदर्शनों को कमज़ोर और ख़त्म करने के लिए अमानवीय हिंसा और अन्य बर्बर तरीके अपना रही हैं। हालिया गिरफ्तारियां उनकी इसी नापाक साज़िश का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शनों को कमज़ोर और बदनाम करने के लिए उन्हें आतंकवादी कार्यवाहियों के रूप में पेश करना है। आज लोग भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी कानून सीएए और देश भर में एनआरसी लाने के मंसूबे के ख़िलाफ एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे हैं। केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही लोगों को पुलिस की बर्बरता और अत्याचारी कार्यवाहियों का सामना करना पड़ा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर एक 8 वर्षीय मासूम सहित अब तक कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें से अधिकतर की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। निर्दोषों के साथ पुलिस का ऐसा हिंसक रवैया पहले कभी नहीं देखा गया है। राज्य से आने वाले वीडियो और दूसरे सबूतों से पता चलता है कि तोड़फोड़ करने में पुलिस ही सबसे आगे रही है और उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के ख़िलाफ अंधाधुंध हिंसा का रवैया अपनाया है। और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए वे निर्दोषों को आरोपी बनाकर पेश कर रहे हैं।

बयान में यूपी सरकार की जुनूनी चालों के ख़िलाफ लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीकों से लड़ाई लड़ने की बात की गई। साथ ही बैठक में सभी वर्गों के लोगों से अपील की गई कि वे बीजेपी शासित राज्यों, विशेषकर यूपी में लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश और निर्दोषों की गैरकानूनी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें।

डॉ० मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली